

उत्तरप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति की राजनीतिक भागीदारी की समीक्षा

शुभम राय

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

सारांश

भारत में 73वें संवधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) समुदायों की राजनीतिक भागीदारी में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है तथा महिलाओं के लिए आरक्षण को अनिवार्य किया गया। अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी वाले उत्तरप्रदेश में इस सुधार ने ग्रामीण शासन की संरचना में गहरा परिवर्तन किया है। यह शोध-पत्र संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बाद उत्तरप्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में SC/ST की राजनीतिक भागीदारी की आलोचनात्मक समीक्षा करता है। इसमें प्रतिनिधित्व सिद्धांत (Pitkin), राजनीतिक भागीदारी सिद्धांत (Verba, Putnam), सशक्तिकरण और अंतर-संबंधिता सिद्धांत (intersectionality) जैसे सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों, सरकारी आँकड़ों और शैक्षणिक साहित्य पर आधारित यह अध्ययन दर्शाता है कि वर्णनात्मक (descriptive) प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु संरचनात्मक असमानताओं, प्रभुत्वशाली वर्गों के नियंत्रण और सामाजिक-राजनीतिक अवरोधों के कारण वास्तविक (substantive) सशक्तिकरण अभी भी असमान और सीमित है। अतः, यह शोध पत्र आरक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने और वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्यशब्द (Keywords): पंचायतीराज, राजनीतिक भागीदारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तरप्रदेश, प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण

प्रस्तावना

भारत के प्राचीन ग्रंथों में स्थानीय स्वशासन की मसालें “सभा”, “समिति” के रूप में मिलती हैं। ब्रिटिश शासन काल में पंचायती संस्थाएं कमजोर पड़ीं, किंतु स्वतंत्रता के बाद गांधीजी, नेहरूजी,

और डॉ. अम्बेडकर ने वकेंद्रीकरण और ग्रामस्वराज पर बल दिया। संवधान निर्माण के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने कहा - “राजनीतिक शक्ति का उपयोग दलतों की सामाजिक मुक्ति के लिए करना चाहिए।”

73वाँ संवधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ था। संवधान में अनुच्छेद 243 से 243(O) तक जोड़े जाने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनके जनसंख्या अनुपात के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों में आरक्षण की गारंटी की गई (अनुच्छेद 243D)। उत्तरप्रदेश, जहाँ SC की आबादी लगभग 20.7% तथा ST की मात्र 0.6% है (जनगणना 2011), इससंदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है।

73वें संवधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243D के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पंचायतों में आरक्षण अनिवार्य किया गया। जिला, क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गईं। उत्तरप्रदेश सरकार ने पंचायतराज अधिनियमों में आवश्यक संशोधन कर इसे मूर्त रूप दिया। पंचायती राज की संरचना: उत्तरप्रदेश में पंचायतीराज त्रिस्तरीय है- {1} ग्रामपंचायत (Village Panchayat) {2} क्षेत्रपंचायत (Block Panchayat) {3} जिलापंचायत (District Panchayat) पंचायतों का पाँच वर्षीय कार्यकाल, प्रत्यक्ष चुनाव, अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण, तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों में आरक्षण प्रमुख विशेषताएँ हैं।

श्रेणी (Category)	संख्या / ववरण (Units/Details)
जिलापंचायत (Zila Panchayats)	75
क्षेत्रपंचायत / मध्यपंचायत (Kshetra / Block Panchayats)	822 लगभग
ग्रामपंचायत (Gram Panchayats)	58,000 to 59,000 लगभग

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की राजनीतिक भागीदारी

भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तरप्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक विशेष अध्ययन क्षेत्र है। राज्य की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ (जनगणना 2011) है, जिस में अनुसूचित जातियों का अनुपात लगभग 20.7% तथा अनुसूचित जनजातियों का मात्र 0.6% है। यह सामाजिक संरचना ही उत्तरप्रदेश को ग्रामीण स्वशासन में आरक्षण और प्रतिनिधित्व के विशेषण के लिए वशष्ठ बनाती है। वंचित वर्ग की राजनीतिक भागीदारी के बिना लोकतंत्र अपूर्ण है (सुरेश

रामवाली) पंचायत स्तर पर **SC/ST** प्रतिनिध ग्राम विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि में भाग लेते हैं। पंचायत चुनावों में **SC/ST** प्रत्याशियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का यह कथन कि “सामाजिक एकता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं” इस तथ्य को रेखांकित करता है कि वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक समानता पूर्व शर्त है (आंबेडकर)। यह शोध इसी संवाद पर केंद्रित है कि संवैधानिक प्रतिनिधित्व का सहदतकवास्तविक सशक्तिकरण में बदल पाया है।

सैद्धांतिक ढाँचा

1. प्रतिनिधित्वका सद्धान्त (Pitkin, 1967): पट कननेवर्णनात्मक (descriptive) और वास्तविक (substantive) प्रतिनिधित्व में भेद किया। आरक्षण के माध्यम से **SC/ST** नेताओं की संख्यात्मक उपस्थिति बढ़ती है, परंतु व्यावहारिक नीति-निर्माण पर वास्तविक प्रभाव डाल पाते हैं, यह प्रश्न बना रहता है।
2. राजनीतिक भागीदारी के मॉडल (Verba, 1995; Putnam, 1993): वर्बाका नागरिक स्वेच्छा चारिता मॉडल (civic voluntarism) संसाधन, प्रेरणा और अवसरों पर बल देता है, जबकि पटनाम सामाजिक पूँजी (social capital) को संस्थागत प्रदर्शन से जोड़ते हैं। इन मॉडलों से **SC/ST** की सीमांत भागीदारी को समझा जा सकता है।
3. सशक्तिकरण और अंतर संबंधिता (Crenshaw, 1989): दलित एवं आदिवासी महिलाएँ जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर बहुस्तरीय हाशियकरण का सामना करती हैं। इनके राजनीतिक अनुभव का अध्ययन केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व से परे जाकर होना चाहिए।
4. नीति मूल्यांकन (Chattopadhyay & Duflo, 2004): प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि आरक्षण सार्वजनिक वस्तुओं के आवंटन पर प्रभाव डालता है, किंतु इसका असर स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर रहता है।

शोधपद्धति

यह शोध मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है: कानूनी दस्तावेज: भारतीय संविधान, 73वाँ संशोधन अधिनियम। सरकारी आँकड़े: जनगणना 2011, राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें। शैक्षणिक साहित्य: रिसर्चगेट, जे-स्टोर, PRIA, NIRD आदि। सैद्धांतिक संदर्भ: Pitkin (1967),

Verba (1995), Putnam (1993), आंबेडकर के वचार, Intersectionality साहित्य। मीडिया वहाल के समाचार—के संरचित समेकन पर आधारित हैं। उत्तरप्रदेश के लए SC/ST जनसांख्यिकी (Census 2011 और लोक सांसद प्रश्नोत्तरी दस्तावेज) तथा व वध राज्य/क्षेत्रीय अध्ययनों का उपयोग किया गया है। प्रमुख स्रोतों के रिवरेंसेस लेख में अंत में दिए गए हैं।

अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व की समीक्षा

1. प्रतिनिधित्व की मात्रा बढ़ी पर गुणवत्ता असमान रही: 73वीं संशोधन के बाद SC/ ST के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी—वशेषकर ग्राम स्तर पर—पर कई अध्ययनों (PRIA, NIRD, व भन्न अकादमिक पेपर) ने संकेत दिया कि यह संख्यात्मक प्रतिनिधित्व हमें शासनात्मक प्रभाव में तब्दील नहीं हुआ; कई बार दलित प्रतिनिधियों को निर्णायक शक्ति, वित्तीय नियंत्रण या प्रशासनिक अधिकार सीमित मिले।
2. दलित महिलाएँ—दुगुनामार्जिनलाइजेशन: अनुसूचित जाति की महिलाओं के लए आरक्षण ने राजनीतिक प्रवेश तो सुनिश्चित किया पर सामाजिक और दमनात्मक संरचनाएँ (ब्राह्मणवादी/पारम्परिक स्थानीय शक्तिसंयन्त्र) कई बार उनकी स्वायत्तता को कम कर देती हैं; कई मामलों में सद्ग्रहित/पछड़े पुरुष या स्थानीय दलित-elite उनके प्रतिनियुक्ति का नियंत्रण करते रहे। क्षेत्रीय अध्ययनों ने यह भी दिखाया कि कुछ स्थानों पर 'proxy' या 'sarpanch-pati' जैसे रूप प्रकट हुए जहाँ वास्तविक निर्णय पुरुष-परिवार-नियंत्रित रहे।
3. सरोकारों का स्वर (Policy priorities): आरक्षित प्रतिनिधियों ने अक्सर सड़कों, पानी, शिक्षा जैसी प्राथमिक सार्वजनिक वस्तुओं को प्राथमिकता दी—पर यह मानक नहीं था; स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य तथा पार्टी-नीतियों का प्रभाव निर्णायक रहा। Chattopadhyay & Duflo जैसे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि उच्चस्तरीय प्रयोग-आधारित शोधों में आरक्षण ने कुछ मामलों में सार्वजनिक गुड्स की गुणवत्ता को बदला।
4. स्थानीय गुटबाज़ी व एलीट-हाइजैक (Elite capture): अनेक अध्ययन बताते हैं कि जहां तक संसाधनों का वितरण है, स्थानीय एलीट—चाहे वे उच्चजाति के हों या दलित-elite—कई बार निर्णयों को नियंत्रित कर लेते हैं; इसका परिणाम यह होता है कि निचले तबके का वास्तविक फायदा सीमित रहता है। यही निष्कर्ष उत्तरप्रदेश के कुछ क्षेत्रीय के सस्टडीज़ में मिलते हैं।

वश्लेषण- सैद्धान्तिक ववैवस्थिक व्याख्या

1. वर्णनात्मक बनाम सामग्रीगत प्रतिनिधित्व: Pitkin के वभाजन के अनुसार उत्तरप्रदेश में 73वीं संशोधन ने वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व (अर्थात् SC/ST के चेहरे का चुनाव) जरूर बढ़ाया, पर सामग्रीगत प्रतिनिधित्व (नीतिगत निर्णयों पर प्रभाव) व भन्न स्तरों पर असमान निकला। कई बार प्रतिनिध संरचनात्मक बाधाओं—शक्षा, आर्थिक संसाधन, प्रशासनिक जानकारी—की वजह से स्वायत्त निर्णय नहीं ले पाते।
2. सामाजिक पूँजी और भागीदारी: Putnam/Verba मॉडल के अनुसार जहाँ सामाजिक पूँजी मजबूत होगी, वहाँ स्थानीय संस्था अधिक प्रभावशाली होंगी। यूपी के अनेक गांवों में जातिगत वभाजन और सामाजिक बहिष्कार ने दलत प्रतिनिधियों की नेटवर्क व सामूहिक दबाव बनाने की क्षमता को सीमित किया। इसलिए प्रतिनिधियों की सफलता का निर्भरत्वव्यक्तिगत गुणों के साथ-साथ सामाजिक-प्रासंगिक संसाधनों पर भी है।
3. अंतर-संबंधिता चुनौतियाँ: दलत महिलाओं को जाति और लिंग दोनों के आधार पर प्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करना पड़ता है— यह न केवल चुनावी सफलता को प्रभावित करता है, बल्कि पद के भीतर उनकी निर्णयक्षमता व सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। कई अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ प्रशिक्षण, कानूनी सुरक्षा व सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य होने चाहिए।
4. राजनीतिक दलों व स्थानीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव: उत्तरप्रदेश में बड़े राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय दलों की स्थानीयस्तर पर रणनीतियाँ (candidate selection, दबाव कारीगठ जोड़, प्रत्याशियों का वृत्त एवं संगठन) दलत नेतृत्व के वास्तविक प्रभाव को प्रभावित करती हैं—कई बार दलत प्रतिनिध पार्टी के भूमिकात्मक आदेशों के अनुरूप कार्य करते हैं। मीडिया वहाला घटनाएँ भी स्थानीय आरक्षण-रूगालयों (roster) और आरक्षण-रिक्तियों पर वाद-ववाद दिखाती हैं।

वचाराधीन चुनौतियाँ

1. शक्षा/संसाधन-खासकमी: निर्वाचित दलत प्रतिनिधियों का औसत साक्षरता/प्रशासनिक प्रशक्षित होना अक्सर कम रहता है, जिससे योजना-लेखन व निध-प्रबंधन में कमजोरी आती है।
2. एलीट-हाइजैक और पारिवारिक/पार्टरल नियंत्रण: 'प्रॉक्सी' नेतृत्व या परिवार-नियंत्रण के कारण महिलाओं व निचले दलत प्रतिनिधियों की स्वायत्तता कमजोर होती है।

3. सामाजिक भेदभाव और धमकियाँ: विशेष कर ववादास्पद या संवेदनशील निर्णयों में जातिगत तनाव उत्पन्न होता है, जिससे प्रतिनिधियों का मनोबल प्रभावित होता है।
4. नियोजितकरण (co-optation) और पार्टी-आदेश: राजनैतिक दलों के दबाव से स्थानीय प्राथमिकताओं का झुकाव बदल सकता है।

नीति-निर्देश और सुधारात्मक सुझाव

1. प्रशिक्षणवक्षमता निर्माण: निर्वाचित SC/ST प्रतिनिधियों के लिए नियमित, मॉड्यूल-आधारित प्रशिक्षण (वर्तनीयप्रबंधन, स्थानीययोजनाएँ, कानूनी अधिकार) अनिवार्य करें। कई सफल-आधारित अध्ययनों ने प्रशिक्षण को निर्णायक बताया है।
2. सामाजिक समर्थन संरचनाएँ: ग्राम स्तरीय सामाजिक पूँजी बढ़ाने के लिए सामुदायिक मंच और ग्राम सभा की सक्रियता पर बल दें—यह दलित प्रतिनिधियों को सामूहिक समर्थन दे सकती है। (Putnam/Verba सद्वांतानुरूप)।
3. कानूनी सुरक्षा व निगरानी: प्रतिनिधियों को धमकी/हिंसा से बचाने हेतु विशेष सुरक्षा प्रावधान व फास्ट-ट्रैक शिकायत निवारण तंत्र बनाना चाहिए।
4. रोटेशन-रूल की पारदर्शिता व पुनरावलोकन: आरक्षण रोलर और सीट-अवसान का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु स्वतन्त्र समीक्षार्थ तथा जनहित सुनवाई आयोजित हों—हाइकोर्ट/SEC मामलों में दिखे मुद्दे ध्यान में लें।
5. विशेष कार्यक्रम दलित महिलाओं के लिए: दलित महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हस्तक्षेप प्रारम्भ किए जाएँ ताकि वे पद में आकर वषयगत निर्णय ले सकें क' प्रॉक्सी' बनकर रह जाएँ।

वमर्श

पटकन का सद्वांत दर्शाता है कि उत्तरप्रदेश ने वर्णनात्मक प्रतिनिधित्वतो प्राप्त कर लिया है, परंतु वास्तविक प्रतिनिधित्व अभी अधूरा है। वर्बा और पटनाम के मॉडल बताते हैं कि संसाधनों की कमी और सामाजिक पूँजी की कमजोरी भागीदारी को सीमित करती है। अंतर-संबंधता (Intersectionality) यह उजागर करती है कि दलित महिलाओं का नेतृत्व अक्सर प्रतीकात्मक रह जाता है।

आंबेडकर का दृष्टिकोण याद दिलाता है कि राजनीतिक लोकतंत्र भी स्थायी हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित हो। चोपाध्याय और डुफ्लो (2004) के अध्ययन भी यह संकेत देते हैं कि आरक्षण नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं, किंतु संस्थागत अवरोध इन के प्रभाव को सीमित कर देते हैं।

निष्कर्ष

उत्तरप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देनेवाले 73वें संशोधन अधिनियम के प्रभाव स्वरूप अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों की राजनीतिक भागीदारी में निरंतर वस्तुतः वृद्धि हुई है। प्रतिनिधित्व के स्तर पर वर्णनात्मक (descriptive) वृद्धि अवश्य हुई है— पंचायतों में SC/ST सदस्यों एवं महिलाओं की हिस्सेदारी व्यापक रूप से बढ़ी है, जिससे लोकतांत्रिक वमर्श में समावेशन और वयधताका सकारात्मक संकेत मिलता है। फिर भी, यह अध्ययन दर्शाता है कि पात्रताओं और संरचना में निहित असमानताओं के कारण यह भागीदारी अभी मुख्यतः प्रतीकात्मक है; वास्तविक नीतिगत (substantive) सशक्तिकरण, निर्णय प्रक्रिया में प्रभाव तथा संसाधनों पर नियंत्रण को वांछित स्तर तक नहीं पहुँचा जा सका है। सामाजिक पूँजी की कमी, शिक्षा/प्रशासनिक संसाधनों की अनुपलब्धता, जातिगत और लैंगिक पूर्वाग्रह, 'proxy' या परिवार-नियंत्रित नेतृत्व जैसी चुनौतियाँ आज भी व्याप्त हैं। उच्चस्तरीय गुटबाजी या स्थानीय एलिटद्वारा संसाधनों का नियंत्रण, और स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं के कारण वंचित समुदायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

इस लिए, केवल आरक्षण नीतियों को लागू करना पर्याप्त नहीं है; आवश्यक है कि प्रशिक्षण, क्षमता-विकास, कानूनी/सामाजिक संरक्षण, ग्राम सभा की सक्रिय सहभागिता एवं सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अंतरसंबंधता (intersectionality), सशक्तिकरण और सार्थक भागीदारी के लिए विशेष कार्यक्रम—विशेषकर दलित एवं आदिवासी महिलाओं के लिए—अत्यंत जरूरी हैं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जागरूकता, और जवाब देहीतंत्र को भी मजबूत किया जाना चाहिए।

अंततः, उत्तरप्रदेश के अनुभव से यह निष्कर्ष निकलता है कि संवैधानिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी महत्वपूर्ण यथार्थ हैं, किंतु सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण की संभावनाएँ तभी पूर्ण होंगी जब संरचनागत अवरोधों के समाधान हेतु बहुस्तरीय नीतिगत हस्तक्षेप सुनिश्चित किए जाएँ। केवल सीटों की गणना ही नहीं, बल्कि प्रतिनिधियों की सहभागिता, आत्मनिर्भरता और निर्णयक्षमता को बढ़ाना; यही पंचायतीराज और सामाजिकन्याय की वास्तविक सफलता का मानक

होगा. आंबेडकर की यह चेतावनी प्रासंगिक है कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक अधिकार स्थायी नहीं हो सकते।

संदर्भ

- i. भारतसरकार. (1992). भारतकासंवधान, 73वां संवधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 243 से 243(O)।
- ii. उत्तरप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम एवं संबंधित सरकारी दस्तावेज।
- iii. उत्तरप्रदेश पंचायतीराज विभाग. (2025). आधिकारिक वेबसाइट
- iv. भारत सरकार। (2011). जनगणना 2011: अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जनसांख्यिकी आंकड़े।
- v. Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- vi. Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- vii. Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- viii. Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.
- ix. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443.
- x. Ambedkar, B. R. (विशेष रूप से दलित राजनीति एवं सामाजिक न्याय पर विचार और लेख)।

-
- xi. शैक्ष णक शोधपत्र (PRIA - People's Research Institute for Inclusive Development; NIRD - National Institute of Rural Development) और अन्य संबंधित शैक्ष णक स्रोत।
- xii. सामाजिक वज्ञान जर्नल: उत्तरप्रदेश के संदर्भ में पंचायतीराज व्यवस्थापर शोध आलेख।
- xiii. स्थानीय शासन और लोकतंत्रपर व भन्न शोध पत्रत थाराज नीतिक सद्धांत संबंधी साहित्य।
- xiv. उत्तरप्रदेश चुनाव आयोग की रिपोर्टें एवं पंचायतीराज चुनाव संबंधित आंकड़े।
- xv. सामाजिकन्याय, दलत एवं आदिवासी सशक्तिकरण पर प्रकाशित साहित्य एवं सरकारी रिपोर्टें।
- xvi. मीडियारिपोर्ट और समाचारपत्र: उत्तरप्रदेश पंचायतीराज से संबंधित विश्लेषण और आरक्षण नीति संबंधी जानकारी।
-